

विचार बिन्दु

योग्य पति अपनी पत्नी को सम्मान की अधिकारिणी बना देता है। –मनु

राजस्थान में कलाओं के विस्तार में ललित कला अकादमी की भूमिका

राजस्थान का नाम लेते ही आँखों के सामने रंगों, रेखाओं, आकृतियों और लोक-स्मृतियों से सजा हुआ एक विराट सांस्कृतिक संसार उभरता है। यहाँ की हवेलियों की भित्तिचित्रकारी, किशनगढ की बणी-ठणी, बूंदी और कोटा की चित्रशैली, मेवाड की लघुचित्र परंपरा, फड चित्रांकन, मांडणा, कठपुतली, लोकमूर्तियाँ, धातु-कला, मृण्मूर्ति और आधुनिक चित्रकला ये सभी राजस्थान की बहुरंगी कला-परंपरा के जीवंत प्रमाण हैं। इस समृद्ध विरासत को संरक्षित करने, कलाकारों को प्रोत्साहन देने तथा कला को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुँचाने में राजस्थान ललित कला अकादमी की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही है।

राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष 1957 में हुई। इसका उद्देश्य प्रदेश में ललित कलाओं का प्रचार-प्रसार करना, कलाकारों की रचनात्मक क्षमता को विकसित करना, कला-परंपराओं का संरक्षण करना और नए कलाकारों को उचित मंच उपलब्ध कराना है। अकादमी जयपुर स्थित अपने परिसर से चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, छायाचित्रण, लोक एवं समकालीन कला जैसी विविध विधाओं को प्रोत्साहित करती है। यह संस्था कलाकार और समाज के बीच एक सुजनात्मक सेतु का कार्य करती है।

राजस्थान की कला-परंपरा का स्वरूप अत्यंत विस्तृत और विविधतापूर्ण है। मरुस्थलीय जीवन, लोकविश्वास, धार्मिक आख्यान, बीरागाथाएँ, प्रकृति, पशु-पक्षी, ग्रामीण जीवन और राजसी संस्कृति यहाँ की कला के प्रमुख विषय रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट चित्रशैलियाँ विकसित हुईं। मेवाड की चित्रकला में धार्मिकता और लोकजीवन को सहजता दिखाई देती है, जबकि बूंदी और कोटा की चित्रशैली में प्रकृति, शिकार और राजदरबार के दृश्य प्रमुख हैं। किशनगढ शैली अपनी कोमल भावाभिव्यक्ति और सौंदर्यबोध के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियों के भित्तिचित्र सामाजिक इतिहास और लोक-संस्कृति के दस्तावेज हैं।

ऐसी समृद्ध परंपराओं को केवल संग्रहालयों तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। उन्हें वर्तमान जीवन से जोड़ना भी आवश्यक है। राजस्थान ललित कला अकादमी इसी दिशा में कार्य करती है। अकादमी पारंपरिक कलाओं के साथ-साथ आधुनिक और प्रयोगधर्मी कला को भी मंच प्रदान करती है। इससे कलाकारों को अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए नए माध्यमों, नई तकनीकों और नए विचारों के साथ सृजन करने का अवसर मिलता है।

अकादमी की सबसे प्रमुख गतिविधियों में कला-प्रदर्शनियों का आयोजन शामिल है। वार्षिक कला प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कलाकारों की अपनी कृतियाँ प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इन प्रदर्शनियों में चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला और अन्य दृश्य कलाओं का समावेश होता है। अनुभवी निर्णायकों द्वारा कृतियों का चयन किया जाता है और श्रेष्ठ कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इससे कलाकारों को पहचान, सम्मान और आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

वार्षिक कला प्रदर्शनी केवल पुरस्कार देने का आयोजन नहीं होती, बल्कि यह प्रदेश के कला-परिदृश्य का वार्षिक मूल्यांकन भी प्रस्तुत करती है। इसमें यह देखा जा सकता है कि कलाकार किन विषयों पर काम कर रहे हैं, उनकी तकनीक में क्या परिवर्तन आ रहे हैं और समाज की बदलती परिस्थितियाँ कला में किस प्रकार अभिव्यक्त हो रही हैं। उदाहरण के लिए, हाल के आयोजनों में शहरी जीवन, पर्यावरण, स्त्री-अनुभव, लोकपरंपरा, वचनपन, ग्रामीण जीवन और सामाजिक परिवर्तन जैसे विषयों को स्थान मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान की कला परंपरा स्थिर नहीं, बल्कि निरंतर विकसित होने वाली जीवंत धारा है।

अकादमी का दूसरा महत्त्वपूर्ण योगदान युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देना है। किसी भी कला-परंपरा की निरंतरता तभी बनी रह सकती है, जब नई पीढ़ी उससे जुड़े। अनेक युवा कलाकार प्रतिभाशाली होते हुए भी आर्थिक कठिनाइयों, उचित मार्गदर्शन और प्रदर्शन के अवसरों के अभाव में पीछे रह जाते हैं। अकादमी प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, कला शिविरों, कार्यशालाओं और पुरस्कारों के माध्यम से ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ने का अवसर देती है।

युवा कलाकारों के लिए कला-शिविर विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। शिविरों में विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकार एक-दूसरे की कार्यशलाओं को समझते हैं और अनुभवों का आदान-प्रदान करते हैं। वरिष्ठ कलाकारों के मार्गदर्शन से युवा कलाकारों को तकनीकी ज्ञान, विषय-विस्तार और प्रस्तुतीकरण की नई दृष्टि प्राप्त होती है। कला केवल एकान्त में बैठकर चित्र बनाने की प्रक्रिया नहीं है; यह संवाद, प्रयोग और सामूहिक अनुभव से भी विकसित होती है। अकादमी के शिविर इस संवाद को संभव बनाते हैं।

अकादमी कला-व्याख्यानों, संगोष्ठियों और परिचर्चाओं के माध्यम से कला के सैद्धांतिक पक्ष को भी मजबूत करती है। कला इतिहास, आधुनिक कला, लोक कला, संरक्षण, संग्रहालय-विज्ञान, कला-बाजार और डिजिटल माध्यमों पर आयोजित कार्यक्रम कलाकारों, विद्यार्थियों और कला-प्रेमियों के लिए ज्ञानवर्धक होते हैं। इससे कला केवल प्रदर्शन की वस्तु न रहकर विचार और विमर्श का विषय बनती है।

राजस्थान की लोक और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण में भी अकादमी की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। मांडणा, फड, लघुचित्र, भित्तिचित्र, लोकमूर्तिकला और पारंपरिक हस्तकला जैसी विधाएँ केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं हैं; उनमें समुदायों की स्मृतियाँ, धार्मिक आस्थाएँ, सामाजिक मान्यताएँ और जीवन-पद्धतियाँ भी सुरक्षित रहती हैं। आधुनिकता और बाजार के दबाव में अनेक पारंपरिक कलाएँ धीरे-धीरे कमजोर हो रही हैं। अकादमी इन कलाओं को प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के माध्यम से नए दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करती है।

लोक कला को समकालीन संदर्भों से जोड़ना भी आवश्यक है। यदि पारंपरिक कला केवल अतीत की वस्तु बनकर रह जाए, तो उसकी जीवंतता समाप्त हो सकती है। अकादमी की भूमिका इस बात में है कि पारंपरिक कलाकारों को नए विषयों, नए बाजारों और नए माध्यमों से जोड़ा जाए। पारंपरिक शैली में पर्यावरण, जल-संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, ग्राम्य विकास और सामाजिक सद्भाव जैसे विषयों को वित्ति्त करया जा सकता है। इससे लोक कला अपने मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए वर्तमान समय से संवाद कर सकेगी।

अकादमी कलाकारों के सम्मान और प्रोत्साहन की परंपरा को भी आगे बढ़ाती है। पुरस्कार किसी कलाकार के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं होते, बल्कि ये उसकी साधना की सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक होते हैं। एक कलाकार वर्षों तक अत्यास, संघर्ष और आत्मसाक्षात्कार के बाद अपनी पहचान बनाता है। जब किसी संस्थागत मंच पर उसकी कृति को सम्मान मिलता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अधिक गंभीरता से सृजन करता है। वरिष्ठ कलाकारों का सम्मान युवा पीढ़ी को यह संदेश देता है कि कला-साधना समाज में प्रतिष्ठित और महत्त्वपूर्ण कार्य है।

अकादमी कला-संग्रह और अभिलेखीकरण के क्षेत्र में भी उपयोगी भूमिका निभा सकती है। किसी भी प्रदेश की कला-धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए कृतियों का संग्रह, कलाकारों का परिचय, कला-शैलियों का दस्तावेजीकरण और प्रदर्शनियों का अभिलेख आवश्यक है। राजस्थान के अनेक कलाकारों ने दशकों तक महत्त्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन उनके जीवन और कृतियों का पर्याप्त दस्तावेजीकरण नहीं हो सका। अकादमी द्वारा कलाकारों की कृतियों का व्यवस्थित अभिलेख तैयार किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ प्रदेश की कला-यात्रा को समझ सकें।

डिजिटल युग में अकादमी की भूमिका और भी व्यापक हो गई है। डिजिटल माध्यमों के कारण कला अब किसी एक शहर या प्रदेश तक सीमित नहीं रहती। ऑनलाइन प्रदर्शनी, डिजिटल संग्रहालय, कलाकारों की डिजिटल प्रोफाइल, आपसी दीर्घाएँ और सामाजिक माध्यमों पर कला-प्रस्तुति के माध्यम से राजस्थान की कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दर्शक मिल सकते हैं।

अकादमी को विद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ भी सक्रिय संबंध स्थापित करने चाहिए। कला शिक्षा केवल चित्र बनाने की तकनीक सिखाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, कल्पनाशक्ति, अवलोकन क्षमता और सौंदर्यबोध विकसित होता है। यदि अकादमी विद्यालयों में कला-शिविर, चित्रकला प्रतियोगिता, लोककला परिचय कार्यक्रम और कलाकारों से संवाद आयोजित करे, तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी कला से जुड़ सकते हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों के विद्यार्थियों तक पहुँचना इस प्रयास की विशेष प्राथमिकता होनी चाहिए।

कला के विस्तार में भौगोलिक विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है। जयपुर राज्य का प्रमुख कला-केंद्र है, लेकिन कला केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, बूंदी, भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर जैसे शहरों में भी कला की समृद्ध परंपराएँ हैं। अकादमी को संभागिय और जिला स्तर पर नियमित प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ और कला संवाद आयोजित करने चाहिए। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को जयपुर तक आने की कठिनाई से मुक्ति मिलेगी।

राजस्थान में कला के विकास के लिए अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय भी जरूरी है। जवाहर कला केंद्र, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय लोक कला मंडल, राजस्थान विश्वविद्यालय, कला महाविद्यालय, संग्रहालय, निजी कला दीर्घाएँ और स्वयंसेवी संस्थाएँ अपने-अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। यदि इन संस्थाओं के बीच साझा कार्यक्रम, संयुक्त प्रदर्शनियाँ, कलाकार विनिमय और शोध परियोजनाएँ संचालित हों, तो कला-जगत को व्यापक लाभ मिल सकता है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय केंद्रों के साथ सहयोग से राजस्थान के कलाकारों को देश के अन्य भागों में भी अवसर मिल सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ललित कला अकादमी प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, व्याख्यानों और कलाकार सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से दृश्य कला को प्रोत्साहित कर सकती है।

अकादमी के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं। कला-प्रदर्शनियों की संख्या बढ़ाना, पारदर्शी चयन प्रक्रिया बनाए रखना, कलाकारों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ग्रामीण कलाकारों तक पहुँचना, कला-बाजार से जोड़ना और स्थायी कला-संग्रह विकसित करना समय की आवश्यकता है। अनेक कलाकार अपनी कृतियों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। अकादमी को कला-विक्रय, कला-परामर्श और ऑनलाइन प्रदर्शनी के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। इससे कलाकारों को आजीविका का सहारा मिलेगा और कला-सृजन अधिक व्यापक होगा।

महिला कलाकारों, दिव्यांग कलाकारों, आदिवासी समुदायों और वंचित वर्गों से आने वाले कलाकारों के लिए विशेष अवसर उपलब्ध करना भी जरूरी है। राजस्थान के जनजातीय अंचलों में अनेक लोककलाएँ और शिल्प परंपराएँ आज भी जीवित हैं। इन कलाकारों की प्रतिभा को मुख्यधारा के कला-मंच से जोड़कर न केवल उन्हें सम्मान दिया जा सकता है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को भी मजबूत किया जा सकता है।

राजस्थान ललित कला अकादमी ने प्रदेश की कला-यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण आधार तैयार किया है। उसने कलाकारों को मंच दिया, प्रदर्शनियों की परंपरा विकसित की, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया और कला को सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनाया। आज आवश्यकता है कि अकादमी अपने कार्यक्षेत्र को और व्यापक बनाए तथा कला को राजधानी से निकालकर प्रदेश के गाँवों, कस्बों और छोटे शहरों तक पहुँचाए।

कला किसी समाज का मौन इतिहास होती है। वह उन अनुभवों की अभिव्यक्ति देती है जिन्हें शब्दों में कहना कठिन होता है। राजस्थान की कला में यहाँ की रेत, लोकजीवन, संघर्ष, आस्था, उत्सव और मानवीय संवेदना का गहरा रंग दिखाई देता है। ललित कला अकादमी इस रंग-संसार की संरक्षक ही नहीं, बल्कि उसकी नई दिशाओं की खोजी भी है। यदि अकादमी परंपरा और आधुनिकता, लोक और शास्त्र, गाँव और शहर तथा कलाकार और दर्शक के बीच सशक्त संवाद स्थापित करती रहे, तो राजस्थान की कला न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी विशिष्ट पहचान और प्रभाव बनाए रखेगी।

–अतिथि संपादक,

अविनाश जोशी,

वरिष्ठ पत्रकार एवं रंत्तभकार



सूर्यप्रताप सिंह राजावत

निर्वाचन आयोग के कामकाज से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण संविधान, कानून, नियम, आधिकारिक अभिलेख, न्यायिक निर्णय और उपलब्ध प्रमाणों की कसौटी पर किया जाना चाहिए। मतदाता सूचियों, निर्वाचन आयुक्तों, मतदाता विवरणों और तकनीक को लेकर प्रश्न उठते हैं। इसलिए तथ्यों, लगाए गए आरोपों, कानूनी स्थिति और उपलब्ध प्रमाणों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग समझना आवश्यक है।

तथ्य : मतदाता सूची की शुद्धता- मतदाता सूची की शुद्धता स्वयं एक वैधानिक आवश्यकता है। Representation of the People Act, 1950 में मतदाता के पंजीकरण, सामान्य निवास, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण तथा वृट्टिपूर्ण या अपात्र प्रविष्टियों के सुधार और विलोपन से संबंधित व्यवस्था है। धारा 19 पंजीकरण का आधार प्रदान करती है। कानून एक व्यक्ति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में अथवा एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकरण को रोकता है। धारा 22 के अंतर्गत प्रविष्टि के संशोधन, स्थानांतरण या विलोपन से पहले उचित सत्यापन की आवश्यकता है। अतः अपात्र, मृत अथवा वृष्णोक्त प्रविष्टियों को हटाना वैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। साथ ही पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से न हटे, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

आरोप या दावा : सॉफ्टवेयर का

संभावित दुरुपयोग-सॉफ्टवेयर के संभावित दुरुपयोग का प्रश्न सार्वजनिक विमर्श में उठाया जाता है। तथ्य यह है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची और निर्वाचन प्रशासन में तकनीक का उपयोग करता है। ERONET जैसी प्रणालियाँ निर्वाचन सूची प्रबंधन में उपयोग की जाती हैं। लेकिन यह अलग और अधिक गंभीर दावा है कि किसी सॉफ्टवेयर को किसी राजनीतिक दल या हित के पक्ष में जानबूझकर तैयार या संचालित किया गया। उपलब्ध सामग्री इस आरोप को स्थापित तथ्य के रूप में सिद्ध नहीं करती। ऐसे आरोप के लिए विशिष्ट तकनीकी या दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक होंगे। इसलिए तकनीक की पारदर्शिता और ऑडिट-योग्यता पर प्रश्न उठाना तथा सॉफ्टवेयर को राजनीतिक रूप से पक्षपाती घोषित करना दो अलग बातें हैं।

तथ्य और कानूनी स्थिति : निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति- Anoop Baranwal v. Union of India (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित चयन व्यवस्था निर्धारित की थी। इसके पश्चात संसद ने Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 पारित किया। इसकी धारा 7 के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता को रखा गया है। यह वैधानिक तथ्य है। इसके विपरीत, यह कहना कि इस परिवर्तन से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता निश्चित रूप से कमजोर हुई है, एक अलग संवैधानिक दावा है। उसका मूल्यांकन कानून, संस्थागत संरचना, सुरक्षा उपायों और

न्यायिक परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए।

तथ्य और कानूनी स्थिति : निर्वाचन आयुक्तों का संरक्षण-2023 के अधिनियम की धारा 16 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के दौरान किए गए कुछ कार्यों, बातों या कृत्यों के संबंध में निर्धारित दीवानी अथवा आपराधिक कार्यवाही से वैधानिक संरक्षण प्रदान करती है। इसे संविधान प्रदत्त प्रत्यक्ष प्रतिरक्षा के बजाय वैधानिक संरक्षण कहना अधिक सटीक है। संरक्षण का अस्तित्व तथ्य है, जबकि उसकी वैधता और सीमा अलग कानूनी प्रश्न हैं। अनुच्छेद 324(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों के संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा का महत्व है।

आरोप या दावा : नामों और वर्तनी के आधार पर बहिष्करण-वर्तनी के मिलान में प्रशासनिक कठिनाई दिखाई देती है। निर्वाचन आयोग के SIR 2026 सर्चपोर्टल पर उल्लेख है कि पुराने और वर्तमान मतदाता रिकॉर्ड में नामों की वर्तनी अलग हो सकती है। मतदाताओं को वैकल्पिक वर्तनी से खोज करने की सलाह दी गई है और “Maneesh” तथा “Manish” जैसे उदाहरण दिए गए हैं। नाम और अन्य विवरणों से भी खोज की सुविधा है। यह रिकॉर्ड के मिलान में वर्तनी और लिप्यंतरण की कठिनाई दर्शाता है। मतदाताओं को वैकल्पिक वर्तनी से खोज करने की सलाह दी गई है और “Maneesh” तथा “Manish” जैसे उदाहरण दिए गए हैं। नाम और अन्य विवरणों से भी खोज की सुविधा है। यह रिकॉर्ड के मिलान में वर्तनी और लिप्यंतरण की कठिनाई दर्शाता है।

तथ्य : प्रवास और सामान्य निवास-Representation of the People Act, 1950 की धारा 20(1A) स्पष्ट करती है कि सामान्य निवास स्थान से अस्थायी

अनुपस्थिति मात्र व्यक्ति को सामान्य निवासी नहीं रहने वाला नहीं बनाती। इसलिए रोजगार, शिक्षा अथवा आजीविका के लिए बाहर रहने वाले व्यक्ति को केवल इस आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता कि वह अपने मूल स्थान पर उपस्थित नहीं है। निर्वाचन आयोग ने पंजीकरण, सुधार, निवास परिवर्तन, विलोपन पर आपत्ति और मतदाता सूची में नाम की जांच जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। अतः सुधारात्मक व्यवस्था का अस्तित्व एक स्थापित तथ्य है।

आरोप या दावा : वृद्ध मतदाताओं और दस्तावेजी असंगतियों का प्रश्न- दस्तावेजी विवरणों में अंतर से मतदाता को कठिनाई की आशंका व्यक्त की जा सकती है। दस्तावेजी असंगतियों वाले नागरिकों की व्यावहारिक कठिनाइयों की जांच उचित है। लेकिन यह दावा कि वृद्ध मतदाताओं को व्यवस्थित रूप से केवल आयु के दस्तावेजी प्रमाण के कारण बाहर किया जा रहा है, उपलब्ध सामग्री से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं कहा जा सकता। प्रशासनिक कठिनाई की संभावना और व्यवस्थित बहिष्करण के आरोप को अलग रखना आवश्यक है।

तथ्य : बिहार SIR पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय-बिहार की Special Intensive Revisions से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का 27 मई 2026 का निर्णय, Association for Democratic Reforms v. Election Commission of India, 2026, इस विमर्श में महत्त्वपूर्ण संदर्भ है। न्यायालय ने मतदाता सूचियों की शुद्धता से संबंधित प्रवास, मृत्यु की सूचना दर्ज न होने और डुप्लीकेट प्रविष्टियों जैसी समस्याओं पर विचार किया। मतदाता सूची की शुद्धता वास्तविक प्रशासनिक और संवैधानिक विषय है। लेकिन किसी समस्या पर न्यायिक विचार का अर्थ यह नहीं है कि निर्वाचन आयोग के विरुद्ध लगाए गए प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध हो जाते हैं।

पैरा 55 में न्यायालय ने कहा कि SIR ve lees Representation of the People Act और 1960 के Rules से टकराती है और न स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की संवैधानिक अनिवार्यता से विचलित होती है। न्यायालय ने को R.P. Act की धारा 21(3) की संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पढ़े जाने पर प्राप्त वैधानिक एवं संवैधानिक अधिकार-क्षेत्र से उत्पन्न प्रक्रिया माना। यह न्यायिक निष्कर्ष के विधिक आधार से संबंधित है; इससे सॉफ्टवेयर के राजनीतिक दुरुपयोग या प्रत्येक हटाए गए नाम के अवैध होने जैसे अलग आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते।

निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुरोक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते। निष्कर्ष